

## वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में महात्मा गाँधी के शैक्षिक चिन्तन की प्रासंगिकता

डॉ० शहादत हुसैन

### सारांश

वैश्वीकरण से दुनिया भर की सभी जातियों, समाज और संस्कृतियों पर न केवल शक्तिशाली प्रभाव पड़ा है वरन तेजी से सूचना और संचार तकनीकी विकास के प्रभाव को जाता है। इसी से वैश्वीकरण में तेजी से वृद्धि हुई है, विभिन्न देशों का समाज भी बहुत तेजी से प्रभावित हुआ है। वैश्वीकरण, आर्थिक विकास, समृद्धि और लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिये दुनिया भर में आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था और प्रवृत्तियों का एकीकरण है, जिसने विश्व की अर्थव्यवस्था के लिये आर्थिक उदारीकरण में एक उदार या मुख्य बाजार की नीतियाँ प्रदान की हैं। इसका उद्देश्य एक एकल विश्व समुदाय की रचना करना है, जहाँ कोई भी सामाजिक संघर्ष नहीं हो और सामाजिक व सांस्कृतिक एकीकरण हो। वैश्वीकरण आर्थिक निजीकरण और राजनीतिक संरचना के बाजारीकरण पर जोर देता है, जिसमें भौगोलिक सीमाओं में कमी होती जा रही है। सरल शब्दों में कहे तो वास्तव में वैश्वीकरण माल-सेवाओं और पूँजी के मुक्त आदान-प्रदान का एक संयोजन है।

प्रस्तावना:-

सामाजिक व्यवस्था को व्यक्ति के विकास के लिये सुविधाजनक और सहयोगात्मक होना चाहिये अन्यथा व्यक्ति के पास विद्रोह करने का अधिकार और कर्तव्य है ताकि वह अपने नये रास्ते खुद बनाये। हाँ ये नये रास्ते सामाजिक ध्येय को ध्यान में रखते हुये बनाये जाने चाहिये, नाकि व्यक्तिगत हितों के लिये। व्यक्ति को प्रेम, अहिंसा, सत्य और न्याय के सिद्धांतों के साथ आध्यात्मिक समाज की संपूर्णता के लिये काम करना चाहिये। सत्य, न्याय और हिंसा के गुणों से रहित समाज/व्यक्ति, समाज के लोगों के आर्थिक और अन्य प्रकार के शोषण को बढ़ावा देते हैं इसलिये राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन का निर्माण सत्य, न्याय और अहिंसा के आधार पर चाहिये परिवार और पारिवारिक नैतिकता, आर्थिक और मूल्य पर आधारित विकास के आधार है। सभी को काम करना चाहिये, यहाँ तक कि एक बौद्धिक कर्मचारी को भी कुछ शारीरिक श्रम अवश्य करना चाहिये। उपयुक्त गुणों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था समाज से सभी तरह के शोषणों तथा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और यहाँ तक कि धार्मिक शोषण को भी दूर करता है।

गाँधी जी के विचारों की प्रासंगिकता को जानने और समझने के लिये उनके द्वारा सुझाये गये मूलभूत शब्दों के अर्थ को समझकर हमें अपने व्यवहार में लाना होगा, क्योंकि विचार दर्शन से प्रवाह हुआ करता है और गाँधी दर्शन के मूल में आपको सत्य अहिंसा, सादगी, अस्तेय, अपरिग्रह, श्रम और नैतिकता मिलेगी। जहाँ से स्थानीय, स्वशासन स्वावलम्बन, स्वदेशी विकेन्द्रीकरण, ट्रस्टीशिप परास्पावलम्बन, सहअस्तित्व, शोषण मुक्त व्यवस्था और सहयोग, सहभागिता व समानता पर आधारित जाग्रति ढाँचे पर अभ्युदाय होगा।

## गाँधीवादी दर्शन और शिक्षा का लक्ष्य



आज भूमंडलीकरण का दौर है और जब राज्य उपनिवेशवाद का स्थान बहु राष्ट्रीय उपनिवेशवाद ने ले रखा है। गाँधी जी राज्य उपनिवेश से लड़े थे। हमें बहुराष्ट्रीय उपनिवेशवाद से जूझना है, क्योंकि दैत्याकार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा देने वाले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और दरअसल

गाँधी के अनुसार विकास के लिये बुनियादी शर्ती थी कि हमारी ज्यादा निर्भती हो निर्णय लेने का अधिकार हमारे हाथों में हो और सारी व्यवस्थाएँ स्वतन्त्र स्फूर्त हो। वास्तव में गाँधी जी वैश्विक महासंघ की परिकल्पना में सभी राष्ट्रों का स्वतंत्र अस्तित्व है और उनके अनुसार किसी भी राष्ट्र को अन्य राष्ट्रों के शोषण की आजादी नहीं रहेगी और न ही कोई राष्ट्र इतना मोहताज या लाचार होगा कि कोई राष्ट्र उसके स्वत्व का दोहन व उसकी संप्रभुता का अपहरण कर सके। गाँधी जी का विचार था कि हमारे दिमाग की खिड़कियां इतनी जरूर खुली होनी चाहिये कि हम बाहर की चीजों का लाभ उठा सकें, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखे कि हमारे दरवाजे इतने न खुल जाये जो बाहर का भी पथ अर्धंड तूफान हमारे अन्दर दाखिल कर के हमारे परखच्चे उड़ा दे। सेमुअल ने गाँधी जी के बारे में कहा कि गाँधी जी अपना नेतृत्व प्रदान कर भारतीय जनता को अपनी कमर सीधा करना सीखाया और अंकिचन दृष्टि से परिस्थितियों का सामना करना सिखाया सचमुच महात्मा गाँधी भारतीय राजनीति और राष्ट्र की महत्वपूर्ण कड़ी हैं।

#### **वर्तमान वैश्विक तालमेल में उच्च शिक्षा की माँग व चुनौतियाँ:-**

आसानी से उपलब्ध होने वाली पक्षपात रहित और जेब पर भारी नहीं पड़ने वाली उच्च शिक्षा के बारे में जब भी बात होगी, तो गुणवत्ता, प्रासंगिकता और रोजगार देने की क्षमता की आवश्यकता उसमें जरूर शामिल होगी। भारत की युवा आबादी का आकार और माँग देखते हुए उसके मानव संसाधन के विकास पर अधिक और लगातार ध्यान देना अनिवार्य हो गया है।

भारत का 2024-25 तक पाँच ट्रिलियन यानी 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति इस बात पर निर्भर करती है कि

उसके शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान युवा भारतीयों को बदलते हुए रोजगार परक बाजार के लिहाज से कितना प्रासंगिक ज्ञान तथा कौशल प्रदान करने की क्षमता रखते हैं। इसके लिए गुणवत्ता, श्रेष्ठता, नवाचार और लगातार उन्नत की जरूरत है। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल पंजीकरण अनुपात (जीईआर) बढ़ाकर कम से कम 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य है, जिसका मतलब है कि दुनिया में चार में से एक स्नातक भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था से ही निकलेगा। फिलहाल सकल पंजीकरण अनुपात केवल 26.3 प्रतिशत है और अगले 15 वर्षों में इसे दोगुना करने के लिए योजना एवं क्रियान्वयन दोनों मोर्चों पर तगड़े सुधार की जरूरत होगी। भारत का यह अनुपात वैश्विक अनुपात (36.7 प्रतिशत) से कम है।

### उच्च शिक्षा—भारत के लिए अहम चुनौतियाँ—

आबादी के लिहाज से भारत फायदे की स्थिति में है। उसके कामकाजी वर्ग की आबादी गैर—कामकाजी आबादी से अधिक हैं। 29 वर्ष की औसत उम्र के साथ यह दुनिया का सबसे युवा देश है और ऐसा उस समय हुआ है, जब बाकी दुनिया बुजुर्ग हो रही है। अमेरिका में औसत कामकाजी उम्र 40 वर्ष है, पश्चिमी यूरोप में 46 और जापान में 47 वर्ष है। इस तरह भारत के पास अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करने के लिए युवा कार्यबल ही नहीं होगा, बल्कि उसके पास कुशल कार्यबल का वैश्विक अड्डा बनने का मौका भी है तथा यही मौका चुनौतियों का भी है। भारतीय युवाओं को शिक्षा तथा कौशल की जरूरत है और भारतीय प्रणाली को इसके लिए पूरी तरह सक्षम बनना होगा।

स्नातकों को रोजगार के कम मौके मिलना, शिक्षण की खराब गुणवत्ता, कमजोर प्रशासन, अपर्याप्त, धन आवंटन और जटिल नियामकीय शर्तों का भारतीय उच्च शिक्षा

क्षेत्र पर असर पड़ता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या आम तौर पर उच्च शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और मजबूती का भरोसेमंद सूचकांक होता है। 2018-19 में केवल 47,427 विदेशी छात्रों ने भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश लिया, जो 950 से अधिक विश्वविद्यालयों वाले देश के लिए पर्याप्त संख्या नहीं है। चीन में 4 लाख से अधिक, जर्मनी में 3 लाख से अधिक और सिंगानपुर में 75,000 से अधिक विदेशी छात्रों ने प्रवेश लिया है। वैश्विक स्तर पर भारत में एक प्रतिशत से कम अंतर्राष्ट्रीय छात्र आते हैं। भारतीय संस्थान प्रतिष्ठित रैंकिंग संस्थाओं द्वारा प्रकाशित दुनिया के 100 शीर्ष विश्वविद्यालय की सूची में जगह भी नहीं पाते। शिक्षा के लिए बाहर जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या भी यहाँ आने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या से 15 गुना अधिक है।

#### वैश्विक तालमेल की भारतीय तस्वीर:-

भारत की हाल ही में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे में शीर्ष 200 वैश्विक विश्वविद्यालय को भारत में अपने विदेशी शाखा परिसर स्थापित करने के लिए न्योता देने का प्रस्ताव है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पाँच वर्ष की कार्य योजना इक्विप (एजुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इनक्लूजन प्रोग्राम) तैयार की है। यह योजना अगले पाँच वर्ष में उच्च शिक्षा प्रणाली का कायाकल्प करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। हाल ही में नीति आयोग ने विदेशी छात्रों की आमद बढ़ाने के उद्देश्य से, बेंगलूरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, चंडीगढ़ और सिक्किम में हिस्सों में विशेष आर्थिक क्षेत्रों में (एसईजेड) की ही तर्ज पर विशिष्ट शिक्षा क्षेत्र (ईईजेड) विकसित करने की सिफरशि भी की है।

शिक्षा की तस्वीर तेजी से बदल रही है, जहाँ दो क्षेत्र मिलते हैं, वहाँ बहुत कुछ रोमांचक हो रहा है। साझेदारी किसी खास क्षेत्र से इतर उन क्षेत्रों में भी हो सकती है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया को बढ़त हासिल है और भारत को जरूरत है मसलन खनन सुरक्षा, जैव अभियांत्रिकी, सिग्नल प्रोसेसिंग, स्वास्थ्य, व्यवस्थाएँ, कृत्रिम मेधा, साइबर, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन आदि। एकीकृत उपाधियों तथा विभिन्न विषयों के अध्ययन में दिलचस्पी बढ़ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों की आबादी 2005 से तीन गुनी हो जाने के बाद भी वहाँ भारत के बारे में जानकारी बहुत कम है। 1996 में ऑस्ट्रेलिया में छह विश्वविद्यालय एक भारतीय भाषा पढ़ाते थे, अब केवल दो ऐसा करते हैं। आपसी सांस्कृतिक समझ का स्तर बढ़ाने और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के लिए जानकारी का मजबूत आधार विकसित करने से ऐसे संबंध और भी प्रगाढ़ हो सकते हैं। इससे दोनों देशों को छात्रों, कॉलेजों एवं केंद्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर विश्वविद्यालयों के लिए साझेदारी की संभावना तलाशने में मदद मिल सकती है।

अंग्रेजी भाषा के शिक्षण एवं प्रशिक्षण, अनुभव के आधार पर सीखने के लिए तकनीक के प्रयोग एवं शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के क्षेत्र में क्षमता निर्माण का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया काफी मजबूत है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जैसे प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों से साझेदारी भी हो सकती है। शोध साझेदारी भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे जल, बुनियादी ढांचे, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रशासन के क्षेत्र में खास समस्याओं का समाधान मिल सकता है। व्यावसायिक एवं पेशेवर शिक्षा पर अधिक जोर देने से भारत को 2022 तक 40 करोड़ कामगारों का कौशल बढ़ाने के तरीके ढूंढने में मदद मिल सकती है। बहरहाल जरूरत

इस बात की है कि सरकारें संभावनाओं के ढेर में से सही चुनाव करने और ऐसे व्यावहारिक अवसर चुनने के लिए प्रदाताओं को लक्षित एवं स्पष्ट सलाह दें जो ऑस्ट्रेलिया की ताकत एवं भारतीयों की जरूरतों के मुताबिक हों। साथ ही खर्च और रोजगार के बारे में भारतीय छात्रों की अपेक्षाओं को भी सावधानी से समझना होगा।

भारत में शैक्षिक सम्पर्क दोनों साझेदारी देशों को फायदा पहुंचाने वाली सच्ची साझेदारी होनी चाहिए, जो विभिन्न नीतिगत संवादों, संस्थागत, साझेदारी, शोध साझेदारी, क्षमता निर्माण के कार्यक्रमों और छात्रों के पंजीकरण पर आधारित हो।

#### उपसंहार:—

महात्मा गाँधी का शिक्षा—दर्शन खास तौर पर बुनियादी शिक्षा के आधारभूत ढाँचे को मजबूत तथा सुदृढ़ बनाने पर आधारित है। इसीलिये गाँधी जी ने अपने शिक्षा—दर्शन को 3R और 3H की संज्ञा दी थी। 3R से उनका आशय Reading, Writing, Arithmetic से था अर्थात् (अंकों का ज्ञान) और 3H से उनका आशय Hand, Head or Heart से था। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बालक का शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करे। गाँधी जी इस बात के आग्रही थे कि शिक्षा को यथासम्भव व्यावहारिक क्रिया—कलापों और अनुभव आधारित होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जितनी अधिक क्रिया—कलाप तथा व्यावहारिक अनुभव पर आधारित होगी विद्यार्थी उतना शीघ्र सीखेगा। केवल यही नहीं विद्यार्थियों का अधिगम व केवल मात्रा में अधिक होगा बल्कि स्थायी तथा दीर्घकालिक भी होगा। हम विकास के पथ पर कितने ही अग्रसर क्यों न हों, गाँधी जी के सिद्धांतों को नकारा नहीं जा सकता। आज साम्प्रदायिक सद्भावना की आवश्यकता ज्यादा है। महात्मा गाँधी का दर्शन न केवल प्रासंगिक है, अपितु वर्तमान की



कई समस्याओं का समाधान भी है। गाँधी जी के सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और नैतिकता के सिद्धांत तो हमेशा ही हमारे लिये उपयोगी रहेंगे।

### सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. गुप्ता, एन०एल०, "शताब्दी में मानवीय मूल्य", अमूल पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
2. सक्सेना, एन०आर०, "स्वरूप एवं पाण्डेय", डॉ० के०पी० शिक्षा दर्शन तथा महान शिक्षा शास्त्री, MISO : 900/2008, 2011, आर० लाल बुक डिपो, मेरठ।
3. एजुकेशन रिकन्सट्रक्शन इन इण्डिया, संचार बुलेटिन, अप्रैल कुमार, विमल-भारत में ब्रिटिश शिक्षा, ग्रीन लीफ पब्लिकेशन बुलामाल, वाराणसी, 2013
4. वर्मा, निर्मल, "निर्मल-विश्व के महान शिक्षाशास्त्र", ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2014
5. भार्गव, महेश एवं दीक्षित नदन्दी, "शिक्षा में नवाचार तथा नवीन प्रवृत्तियाँ", एच०पी० भार्गव बुक हाउस, कचहरी घाट, आगरा, 2015
6. सक्सेना, एस०, "शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि" साहित्य प्रकाशन, आगरा, 2015
7. पाल, प्रो० हंस राज, "उच्च शिक्षा में अध्यापन एवं प्रशिक्षण की प्रविधियाँ", हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, जुलाई, 2015
8. One weak faculty Development programme/workshop in Meerut College, Meerut, Press, 27 Dec. 2018 to 2 Jan. 2019.
9. <https://www.orfonline.org/expert-speak/increasing-enrolment-in-higher-education-a-quantitative-and-quantitative-challenge-55883/> (accessed on 8 January, 2018).
10. <https://ministers.education.gov.au/tehan/growing-engagement-between-australia-and-india> (accessed on 8 January, 2018)
11. <https://www.afr.com/policy/health-and-education/australia-s-education-approach-to-india-not-sustainable-20190428-p5i0c> (accessed on 8 January, 2018).